**भारत सरकार**
**सहकारिता मंत्रालय**

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1602**

21 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

## प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं का डिजिटलीकरण

**1602 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः**

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं (पीएसीएस) के डिजिटलीकरण की योजना/परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और पीएसीएस के डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) क्या ये संस्थाएं एक सामान्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के सामान्य सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म के अंतर्गत डिजिटलीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिनांक 29 जून, 2022 के निर्णय के माध्यम से 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से देशभर में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है ।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण से अनेक लाभ प्राप्त होंगें जैसे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होगा, लेनदेन लागतों में कमी होगी, भुगतानों के असंतुलनों में कमी आएगी, जिला केन्द्रीय सहकारी समितियों व राज्य सहकारी समितियों के साथ निर्बाध लेखांकन होगा और पारदर्शिता में वृद्धि होगी । कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के कार्यान्वयन से पैक्स अपना कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के लिए जिला केन्द्रीय सहकारी समितियों व राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन/ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।

*****